आईपीओ से 882 करोड़ रुपये जुटाएगी उज्जीवन फाइनैंशियल

विदेशी शेयरधारिता घटकर 45 फीसदी रह जाएगी

नूपुर आनंद
मुंबई, 22 अप्रैल

उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज को भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक तौर पर छोटे वित्तीय बैंक का लाइसेंस मिला है और इसकी योजना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए 882 करोड़ रुपये जुटाने की है। एक ओर जहां 358 करोड़ रुपये नए इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे, वहीं बाकी 2.49 करोड़ इक्विटी शेयर पुराने होंगे। यह इश्यू 28 अप्रैल को खुलेगा और 2 मई को बंद होगा। इसका कीमत दायरा 207-210 रुपये है।

कंपनी ने प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 292 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसके बाद विदेशी शेयरधारिता 77 फीसदी के मुकाबले घटकर 45 फीसदी रह जाएगी। परिचालन शुरू करने से पहले उज्जीवन व इक्विटास जैसे लेनदारों को बाजार का सहारा लेना पड़ा ताकि आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत विदेशी शेयरधारिता घटाकर

यह इश्यू 28 अप्रैल को खुलेगा और 2 मई को बंद होगा

49 फीसदी से नीचे लाया जा सके।

छोटे वित्तीय बैंकों के लिए विदेशी शेयरधारिता नियम उसी तरह के हैं जैसा कि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए एफडीआई के नियम हैं। अभी निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वत: मार्ग से विदेशी शेयरधारिता 49 फीसदी तक हो सकती है और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी के जरिए इसे बढ़ाकर 74 फीसदी किया जा सकता है। दिसंबर 2015 के आखिर में उज्जीवन की प्रबंधनाधीन संपत्तियां 4540 करोड़ रुपये थी जबकि सकल गैर-निष्पादित आस्तियां इस रकम का 0.15 फीसदी थीं।

प्रबंधन ने कहा कि इस क्षेत्र में उसकी बाजार हिस्सेदारी 11.15 फीसदी थी और सितंबर 2015 के आखिर में यह कर्ज वितरण के मामले में तीसरा सबसे बड़ी गैर-बैंक वित्तीय कंपनी/माइक्रो फाइनैंस संस्थान था।

मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा सुरेश ने कहा, हम अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में परिचालन शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। हम अपनी क्षमता बना रहे हैं और कोर बैंकिंग सिस्टम और ट्रेजरी परिचालन भी तैयार किया है। निकट भविष्य में बैंक का मुनाफा दबाव में रह सकता है, लेकिन इसे फंड की घटती लागत का फायदा मिलेगा। आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पूंजी आधार के लिए किया जाएगा।

कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऐक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल और कार्वी इसके लीड मैनेजर हैं। पिछले साल आरबीआई ने छोटे वित्तीय बैंक का लाइसेंस 72 में से 10 आवेदकों को दिया था। ये वित्तीय बैंक मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही होंगे और यहां आधारभूत बैंकिंग सुविधा मिलेगी।